



2026:AHC-LKO:6382-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ

प्रतिवेद्य

सुरक्षित: 30.10.2025

पारित: 29.01.2026

आपराधिक अपील संख्या - 84 वर्ष 2010

एवं अन्य सम्बद्ध वाद

कल्लू @ राज कुमार और एक अन्य... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... प्रतिपक्षी

माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति श्री श्रीमती बबिता रानी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए अधिवक्ता: - राजीव सिंह, कुंवर मुकुल राकेश, कुंवर सुशांत प्रकाश, स्मृति

प्रतिपक्षी(ओं) के लिए अधिवक्ता: - शासकीय अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री श्रीमती बबिता रानी द्वारा उद्घोषित)

1. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुंवर मुकुल राकेश को, जिनकी सहायता श्री कुंवर सुशांत प्रकाश द्वारा की गई, विद्वान न्यायमित्र श्री हरिश चन्द्र तथा विदुषी अधिवक्ता सुश्री स्मृति को सुना गया। आपराधिक अपील संख्या 84 सन् 2010, 2695 सन् 2009 एवं 212 सन् 2010 में राज्य की ओर से क्रमशः विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री उमेश वर्मा तथा श्री जी.डी. भट्ट को सुना गया।
2. यह संयुक्त निर्णय आपराधिक अपील संख्या 2695 सन् 2009 (छत्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), आपराधिक अपील संख्या 84 सन् 2010 (राजकुमार उर्फ कल्लू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) तथा आपराधिक अपील संख्या 212 सन् 2010 (ओंकार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) का निस्तारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा, जिन्हें विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, उन्नाव द्वारा विचारण संख्या 181/2005, राज्य बनाम छत्रपाल एवं अन्य, अपराध संख्या 1022/2004, थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.10.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 396 एवं 412 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 396 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा ₹20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो वर्ष के साधारण कारावास का दण्डादेश पारित किया गया। तथापि, अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 412 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। अभियुक्त ओंकार को उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत अभिलिखित दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त छत्रपाल, कल्लू, मन्नीलाल एवं खुशीराम द्वारा वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं।

3. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-2), सूचनाकर्ता अ०सा०-3 बलवंत सिंह द्वारा 25.7.2004 को सुबह 3:15 बजे कृष्ण शर्मा के अंगूठे के निशान के साथ उनके द्वारा लिखी गई तहरीर (प्रदर्श क-1) के आधार पर थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में दर्ज की गई थी।

4. इन अपीलों के निपटान के उद्देश्य से प्रासंगिक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 24/25.7.2004 को 2:30 बजे, जब श्रीमती कृष्णा शर्मा और उनके परिवार के सदस्य अपने घर की छत पर सो रहे थे, कुछ अज्ञात अपराधी अवैध रूप से उनके घर में घुस गए और लाठियों और डंडों (प्रदर्श क-8 और क-9) के साथ छत पर पहुंच गए। उनके बेटे वेद प्रकाश और पति शिवकुमार द्वारा विरोध किए जाने पर, अज्ञात अपराधियों ने उन सभी पर लाठियों और डंडे से हमला किया और कृष्णा देवी, कल्पना, वेद प्रकाश और शिव कुमार को कई गंभीर और घातक चोटें दीं और घटनास्थल से भाग गए। जब घायल पीड़ितों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब घायल लोगों में से एक वेद प्रकाश ने रास्ते में दम तोड़ दिया और कल्पना और शिवकुमार को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल, कानपुर रेफर कर दिया गया क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। इस बीच, कृष्णा शर्मा को उन्नाव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

5. उपरोक्त तहरीर (प्रदर्श क-1) के आधार पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 (भ०द०वि०) की धारा 460 के तहत 25.07.2004 को सुबह 3:15 बजे मामला दर्ज किया गया था। विवेचना की कार्यवाही

शुरू की गई और विवेचना के दौरान, धारा 460 भ०द०वि० के तहत अपराध को धारा 396 भ०द०वि० में बदल दिया गया। घायलों की मौत के बाद कल्पना शर्मा, वेद प्रकाश और शिव कुमार की जांच की कार्यवाही और शवों का शव परीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान, चश्मदीद गवाह कुमारी शैल (अ०सा०-2) और घायल कृष्णा शर्मा (अ०सा०-1) का बयान दर्ज किया गया। अभियुक्त, कल्लू @ राजकुमार और छत्र पाल को 07.08.2004 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने खुलासा बयान दिया और इसके परिणामस्वरूप, आरोपी की ओर इशारा करने पर बरामदगी प्रभावित हुई।

6. आरोपी खुशी राम को 09.08.2004 को गिरफ्तार किया गया था और उसने एक खुलासा बयान भी दिया था जिससे लूटी गई वस्तुओं और अपराध में इस्तेमाल किए गए डंडा की बरामदगी हुई। चूंकि आरोपी कल्लू, छत्रपाल और खुशी राम के इकबालिया बयानों में आरोपी सुरेश बंगाली और मान सिंह के नाम सामने आए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कृष्णा शर्मा और कुमारी शैल की उपस्थिति में आयोजित पहचान परेड का परीक्षण किया गया। कृष्णा शर्मा और कुमारी शैल द्वारा आरोपी के रूप में पहचान नहीं किए जाने पर दोनों के खिलाफ जांच बंद कर दी गई।

7. चूंकि विवेचना के दौरान शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इसलिए आवश्यक विवेचना और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, आरोपी छत्र पाल, कल्लू और खुशी राम के खिलाफ धारा 396 और 412 भ०द०वि० के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (द०प्र०स०) की धारा 173 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद आरोपी ओमकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ विवेचना पूरी होने के बाद उसके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।

8. आरोपपत्र की प्रतियां आरोपी को उपलब्ध कराई गईं। मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। धारा 396 और 412 भ०द०वि० के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े प्रथम दृष्टया मामले का पता चलने पर, आरोपियों के अनुसार आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

9. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों से पूछताछ की, अर्थात् कृष्णा शर्मा (अ०सा०-1), कुमारी शैल (अ०सा०-2), बलवंत सिंह (अ०सा०-3), विश्वनाथ (अ०सा०-4), डॉ. रमेशपति तिवारी (अ०सा०-5), इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्रा (अ०सा०-6), इंस्पेक्टर सुरेश बाबू (अ०सा०-7), इंस्पेक्टर सूर्यनाथ यादव (अ०सा०-8), डॉ अनिल कुमार तिवारी (अ०सा०-9), प्रभारी



निरीक्षक (अ०सा०-10), छोटेलाल पाल (अ०सा०-11) और डॉ राम किशोर (अ०सा०-12) कुल मिलाकर, दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा करने के अलावा, और उसके बाद, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा बंद कर दिया गया था।

10. इसके बाद, धारा 313 द०प्र०स० के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और अपने खिलाफ आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया। हालांकि, आरोपियों ने अपनी बेगुनाही के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश करने का फैसला किया। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उच्च अधिकारियों को संबोधित टेलीग्राम की प्रतियां दायर कीं।

11. अभिलेखों पर प्रस्तुत किए गए सबूतों के मूल्यांकन और अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की ओर से उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने धारा 412 भ०द०वि० के तहत अपीलकर्ताओं को बरी करते हुए, उन्हें धारा 396 भ०द०वि० के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया और उन्हें 13.10.2009 के फैसले और आदेश के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सह-आरोपी ओमकार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

12. आक्षेपित निर्णय और दिनांक 13.10.2009 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत अपील दायर की है।

13. हालांकि इस मामले में बार भर में उन्नत तर्क पर्याप्त हैं, लेकिन हम केवल उन तर्कों से निपटने का प्रस्ताव करते हैं जिनका मामले के गुणों पर असर पड़ता है।

14. अपीलकर्ताओं के वकीलों ने जोरदार तर्क दिया कि सजा की मात्रा पर दोषसिद्धि और आदेश के आक्षेपित निर्णय को रद्द करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष अभिलेखों पर प्रस्तुत साक्ष्य की गलत मूल्यांकन पर आधारित थे। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कई भौतिक कमियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसने अभियोजन की कहानी को अत्यधिक असंभव और संदिग्ध बना दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटे टाइम और एंटे डेटेड है, जो स्पष्ट रूप से अभिलेखों के अवलोकन से और अ०सा०-3 और अ०सा०-4 के बयानों में भौतिक विरोधाभासों से उभरती है, लेकिन इस तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में संबोधित नहीं किया गया है। तर्कों में इस बात पर और जोर दिया गया है कि यद्यपि घटनास्थल पर अ०सा०-1 और अ०सा०-2 की उपस्थिति विवादित नहीं हो सकती है, लेकिन अपराध करने में



अभियुक्तों की मिलीभगत और रात के अंधेरे में अभियुक्त की उनकी पहचान के बारे में उनके साक्ष्य अत्यधिक असंभव, अप्राकृतिक और किसी भी श्रेय के योग्य नहीं थे। अभिलेखों पर प्रकाश का कोई स्रोत स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए, अ०सा०-1 और अ०सा०-2 के लिए वास्तविक अपराधियों की पहचान करने का कोई अवसर नहीं था।

15. इस संबंध में, यह कहना उचित है कि एक आपराधिक मामले में प्राथमिकी के महत्व के बारे में कानूनी स्थिति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा कई अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसा ही एक उदाहरण **थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) 3 एस.सी.सी. 393**, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"12.... एक आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमे में पेश किए गए मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है। उपरोक्त रिपोर्ट के महत्व को अभियुक्त के दृष्टिकोण से शायद ही कम करके आंका जा सकता है। किसी अपराध के गठन के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट को शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम भी हैं।"

16. यह जोरदार तर्क दिया गया कि धारा 396 भ०द०वि० के तहत दंडनीय अपराध के लिए, दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए अपराध में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए और इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 396 भ०द०वि० को लागू करने और लागू करने में गलती की। तदनुसार, दोषसिद्धि और सजा पर आदेश के निर्णय को केवल इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। **मनमीत सिंह उर्फ गोल्डी बनाम पंजाब राज्य 2015 (7) एस.सी.सी. 167** के फैसले पर अवलंबन किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए धारा 396 भ०द०वि० के तहत लगाए गए आरोपों को अस्थिर पाया क्योंकि अपराध के गठन में पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता का तथ्य साबित नहीं हुआ था।

17. इस संबंध में आगे **राज कुमार उर्फ राजू बनाम उत्तरांचल राज्य (अब उत्तराखंड) 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 631** पर अवलंबन किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने यह निर्णय दिया था कि डकैती के अपराध को पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता के प्रभाव के निष्कर्ष के अभाव में स्थापित नहीं कहा जा सकता है।

18. अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि धारा 396 भ०द०वि० के तहत अपराध से संबंधित अभिलेखों पर किसी भी सामग्री के अभाव में, विवेचनाधिकारी ने धारा 396 और 412 भ०द०वि० के तहत केवल तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आगे तर्क यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि धारा 396 भ०द०वि० के तत्व संतुष्ट नहीं थे, संबंधित न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए, इसे सत्र न्यायालय और सत्र न्यायालय में सौंप दिया, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनमीत सिंह (उपरोक्त) और राज कुमार (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के आलोक में रद्द किया जाना चाहिए।

19. आगे का तर्क यह है कि विवेचनाधिकारी ने लापरवाही से विवेचना की है और विवेचना के दौरान अपीलकर्ताओं से संबंधित कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी। यदि विवेचना के दौरान, कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, तो न्यायालय में पहली बार आरोपी की पहचान करने वाले गवाह को न तो विश्वसनीय माना जा सकता है, न ही इस तरह की पहचान के आधार पर किसी भी दोषसिद्धि को आधार बनाना उचित है।

20. आपराधिक न्यायशास्त्र में परीक्षण पहचान परेड के महत्व पर अदालतों द्वारा मामलों के एक कैटिना में चर्चा की गई है। परीक्षण पहचान परेड जांच का एक अनिवार्य तत्व है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, **दाना यादव @ दाहू बनाम बिहार राज्य, (2002) 7 एस.सी.सी. 295 दाहू** के मामले में जांच का एक अनिवार्य तत्व है में न्यायालय में पहली बार पहचान के साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"38. ऊपर विश्लेषण किए गए कानून को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं: -

(ए) यदि कोई अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों को पहले से अच्छी तरह से जानता है, तो कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं बुलाई जाती है और इसे आयोजित करना अर्थहीन और सार्वजनिक समय की बर्बादी होगी।

XXX



(ई) परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाती है, बल्कि कानून में बहुत स्वीकार्य है, लेकिन आमतौर पर न्यायालय में पहली बार एक गवाह द्वारा एक आरोपी की पहचान दोषसिद्धि का आधार नहीं बनना चाहिए, वही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र की प्रकृति से है जब तक कि यह परीक्षण पहचान परेड या किसी अन्य में उसकी पिछली पहचान से गवाही की पुष्टि नहीं की जाती है। परीक्षण पहचान परेड में पिछली पहचान एक गवाह द्वारा एक आरोपी की न्यायालय में पहचान के साक्ष्य के लिए एक चेक वाल्व है और यह विवेक का नियम है, न कि कानून का।

(च) केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, न्यायालय में पहली बार पहचान के साक्ष्य, परीक्षण पहचान परेड या किसी अन्य साक्ष्य में पिछली पहचान की पुष्टि किए बिना, दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं।

(छ) आमतौर पर, यदि किसी अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, तो न्यायालय में गवाहों द्वारा उसकी पहचान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब उन्होंने पुलिस के समक्ष अभियुक्त के नाम का खुलासा नहीं किया हो, लेकिन इस सामान्य नियम के लिए अपवाद हो सकते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। (महत्व सन्निविष्ट)

21. यह भी तर्क दिया गया है कि कृष्णा शर्मा अ०सा०-1 से संबंधित चिकित्सा साक्ष्य ने यह स्थापित नहीं किया कि वह अपराध के गठन के दौरान घायल हो गई थी क्योंकि उसे आकस्मिक रजिस्टर के माध्यम से भर्ती कराया गया है। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता कल्लू और मन्नीलाल को अवैध हिरासत में रखा गया था और अंततः 07.08.2004 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके अनुसार उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उच्चाधिकारियों को टेलीग्राम भेजे गए थे, लेकिन विचारण न्यायालय इन तथ्यों और परिस्थितियों की मूल्यांकन करने में विफल रहा और दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और केवल सनक और वहम के आधार पर सजा का आदेश दर्ज किया। आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों की अनदेखी की। मुकदमे के दौरान, धारा 313 द०प्र०स० के तहत आरोपी का बयान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज नहीं किया गया था और इसलिए आरोपी सुनवाई के उचित अवसर का लाभ नहीं उठा सका। इन व्यापक प्रस्तुतियों के साथ, यह तर्क दिया गया था कि आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना था, अपीलों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को स्वीकार किया जाना चाहिए, और अपीलकर्ताओं को उन अपराधों से बरी कर दिया गया जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और दोषी ठहराया गया था। तर्क को मजबूत करने के लिए, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने मनमीत सिंह उर्फ गोल्डी बनाम के फैसलों पर अवलंबन किया। पंजाब राज्य, 2015 (7) एस.सी.सी. 167; मारुदनल ऑगस्टी बनाम केरल राज्य 1979 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 199; कालीचरण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1718; डॉ. एस. एल. गोस्वामी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1972 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 11 और हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य को संदर्भित किया।

22. तत्स्य विपरीत, प्रतिपक्षी के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया था। बता दें कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर अच्छी तरह से चर्चा की गई और तर्क दिया गया। अभिलेखों पर पेश किए गए सबूतों की उचित रूप से मूल्यांकन की गई है और इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सका है। अंसा०-1 और अंसा०-2 की गवाही से, अपराध के गठन में अभियुक्त की मिलीभगत पूरी तरह से स्थापित हो गई है और अंसा०-1 और अंसा०-2 की गवाही में आरोपी की पहचान के संबंध में कोई विरोधाभास अभिलेखों पर सामने नहीं आया है। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि डकैती का अपराध करते समय, आरोपी ने न केवल अंसा०-1 को, बल्कि उसके पति, बेटे और बहू को भी इतने क्रूर तरीके से चोटें पहुंचाई कि कुछ ही समय बाद, उन तीनों अर्थात् शिव कुमार, वेद प्रकाश और कल्पना की मृत्यु हो गई और एकमात्र जीवित घायल कृष्णा देवी को इलाज के लिए लगभग एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जा सकती है।

23. हमने अपीलकर्ताओं और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर उचित विचार-विमर्श किया है और उनकी सक्षम सहायता से अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्रियों की जांच की है।

निष्कर्ष:-

24. माना जाता है कि अपराध रात में किया गया था जब लगभग हर सामान्य व्यक्ति को गहरी नींद में होना चाहिए था। अभियोजन पक्ष का संस्करण, जो विवाद में नहीं है, यह है कि 24/25.07.2004 को, जब श्रीमती कृष्णा शर्मा लगभग 2:30 बजे अपने परिवार के साथ अपने घर की छत पर सो रही थीं, कुछ अज्ञात अपराधी उनके घर में घुस गए और डकैती का अपराध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। अपराध करने के दौरान और परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप, अपराधियों ने अंधाधुंध लाठी-डंडे से हमला किया, जो वे अपराध के समय ले जा रहे थे और परिणामस्वरूप, कृष्णा शर्मा के पति शिव कुमार, उनके बेटे वेद प्रकाश और बहू कल्पना की घटना के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई और कृष्णा को जानलेवा चोटें आईं। अंसा०-1 को सुबह करीब 4.40 बजे सिविल अस्पताल, उन्नाव में भर्ती कराया गया था।

25. अंसा०-3 द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित थाना में लगभग 3:15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्राथमिकी में आरोपी व्यक्तियों का नाम नहीं था और प्राथमिकी दर्ज करने के समय, वे सूचनाकर्ता अंसा०-3 को नहीं जानते थे। विवेचना के दौरान अपीलकर्ताओं का नाम सामने आया।

26. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विवेचना वरिष्ठ निरीक्षक श्री राम को सौंपी गई, जिन्होंने मृतक वेद प्रकाश की जांच की कार्यवाही की थी और पंचनामा रिपोर्ट तैयार की थी। पंचनामा के दौरान, उन्होंने प्रदर्श क-7 के माध्यम से घटनास्थल की नक्शा नज़री तैयार की। 27.07.2004 को जांच निरीक्षक सुरेश बाबू अंसा०-7 को सौंपी गई। विवेचना संभालने के बाद, अंसा०-7 ने अंसा०-2 और उसके बाद अंसा०-1 का बयान दर्ज किया। अंसा०-1 और अंसा०-2 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, विवेचनाधिकारी अंसा०-7 ने आरोपी कल्लू और छत्र पाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने प्रकटीकरण बयान दिया और इसके परिणामस्वरूप, लूटे गए सामान और डंडों की बरामदगी क्रमशः फ़र्द बरामदगी प्रदर्श क-8, क-10 और क-6 के माध्यम से प्रभावित हुई, जो अपराध के गठन में इस्तेमाल किए गए थे, जो प्रकटीकरण बयानों के अनुसरण में खोजे गए थे। ऊपर नामित अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर, शेष अभियुक्तों, अर्थात् सुरेश बंगाली और मानसिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पहचान परेड जेल में पहचान मजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी और तदनुसार, आरोपी सुरेश बंगाली और मान सिंह को पहचान परेड में शामिल किया गया था, लेकिन घायल अंसा०-1 और चश्मदीद गवाह अंसा०-2 द्वारा उनकी पहचान नहीं की गई थी। उन्हें अपराध करने के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, जिससे उन्हें निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत का लाभ मिल रहा था, जबकि अपीलकर्ताओं को मुकदमे का सामना करना पड़ा।

27. मुकदमे के दौरान, घायल कृष्णा देवी का अंसा०-1 के रूप में और कुमारी शैल का अंसा०-2 के रूप में बयान दर्ज किया गया और अंसा०-1 और अंसा०-2 के बयान और अन्य आपत्तिजनक



परिस्थितियों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।

28. वर्तमान वाद में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक था कि शिवकुमार, वेद प्रकाश एवं कल्पना शर्मा की मृत्यु अभियुक्तों द्वारा कारित घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई तथा कृष्णा शर्मा को घटना में गंभीर (grievous) चोटें आईं। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य, अर्थात् पीडब्ल्यू-5 डॉ. रमेश पति तिवारी तथा पीडब्ल्यू-9 डॉ. अनिल कुमार तिवारी, जिन्होंने मृतका कल्पना, मृतक शिवकुमार एवं मृतक वेद प्रकाश का शव परीक्षण किया तथा क्रमशः प्रदर्श क-4, क-5 एवं क-11 के रूप में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, के साक्ष्य के अवलोकन से तथा उपर्युक्त मृतकों की पंचायतनामा रिपोर्ट, जिसे पीडब्ल्यू-10 प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह द्वारा क्रमशः प्रदर्श क-13, क-17 एवं क-23 के रूप में तैयार किया गया, से यह सिद्ध होता है कि तीनों मृतकों की मृत्यु का कारण उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर आई बहुविध चोटें थीं। उक्त सभी चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की पाई गईं तथा स्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं। अभियोजन का कथन था कि उक्त चोटें अभियुक्तों द्वारा लाठी एवं डण्डे से किए गए प्रहार के कारण पीड़ितों को लगी थीं। सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्टों से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके सिर तथा शरीर के अन्य भागों पर अनेक विदीर्ण घाव पाए गए थे, जिनके परिणामस्वरूप सिर की अस्थियों (हड्डियों) में फ्रैक्चर भी हो गया था। यह अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है कि मृतक को दुर्घटना में चोटें आई हैं। चोटों की प्रकृति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह आकस्मिक या स्वयं नहीं हो सकता है। इन चोटों के संबंध में अ०सा०-5 और अ०सा०-9 की गवाही अटूट और बेदाग बनी हुई है, जिन्होंने देखा कि पीड़ितों को लगी चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और मृत्यु सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी। इसलिए, यह तथ्य साबित हुआ कि मृतक शिव कुमार, वेद प्रकाश और कल्पना की मृत्यु कठोर और कुंद वस्तु के कारण लगी चोटों के कारण हुई थी।

29. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या समय, स्थान और घटना अभिलेखों पर स्थापित की गई है और क्या इस संबंध में विचारण न्यायालय की टिप्पणी में कोई त्रुटि है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध वर्ष 25.07.2004 की सुबह लगभग 2:30 बजे हुआ था, जब कृष्णा शर्मा और उसका पूरा परिवार घर की छत पर सो रहा था। बहस के दौरान, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपराध के समय, तारीख और स्थान की सीमा तक अभियोजन



पक्ष के संस्करण पर हमला नहीं किया। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं किया जा रहा है और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार, इस संबंध में विचारण न्यायालय की टिप्पणियों में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाई गई है।

30. चूंकि उपरोक्त चर्चा में, यह विवाद में नहीं है कि घटना संबंधित तिथि, समय और स्थान पर हुई जिसके दौरान पीड़ितों को मार दिया गया था, अब सवाल यह है कि क्या घटना आरोपी द्वारा की गई थी और क्या घटना के लिए आरोपी को जिम्मेदार ठहराकर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा उचित है या नहीं। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और एक अच्छी तरह से तर्कसंगत अवलोकन लाने के लिए, हमें स्वतंत्र गवाहों की गवाही और अपीलकर्ताओं के प्रकटीकरण और किए गए अपराध से संबंधित उसकी बरामदगी के माध्यम से लिया गया है।

31. सबसे पहले, इस न्यायालय को समय-समय पर प्राथमिकी और अपीलकर्ताओं की कथित झूठी भागीदारी के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा पेश की गई दलीलों के आलोक में अभिलेखों पर उपलब्ध परिस्थितियों का आकलन करना होगा। अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि अपराध अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया था और अपीलकर्ताओं के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं होने के बावजूद मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। मुकदमे के दौरान, इस मामले में एक अलग कहानी सामने लाई गई है और अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ गवाही देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट की कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है। आगे तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया है और अंसा०-1, जिसे घायल और घटना का चश्मदीद गवाह कहा जाता है, ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। इसके परिणाम के रूप में, सूचनाकर्ता अंसा०-3 ने भी अपनी इच्छा से या घायल कृष्णा शर्मा के आदेश के तहत तहरीर लिखने के तथ्य को अस्वीकार कर दिया, बल्कि कहा है कि उसने पुलिस के आदेश के तहत तहरीर लिखी थी, इसलिए, अंसा०-1 और अंसा०-3 की गवाही अपने आप में अभियोजन पक्ष के लिए हानिकारक है और इसने मामले की जड़ों को झटका दिया है।

32. इस सबमिशन के आलोक में, अभिलेखों की जांच करने पर, यह पाया गया कि अंसा०-1 ने विशेष रूप से गवाही दी कि उसने कभी भी अंसा०-3 बलवंत सिंह को प्राथमिकी की शर्तों को निर्धारित नहीं किया, न ही उसने इस आशय का अपना बयान विवेचनाधिकारी अंसा०-7 को दर्ज कराया। उसने गवाही दी है कि उसके व्यक्ति पर लगी चोटों के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गई थी और अस्पताल में ही होश आ सकती थी। तहरीर पर उसके अंगूठे के निशान के संबंध में,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसने जवाब दिया कि जब उसे चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो संबंधित पुलिस ने कागज के एक कोरे टुकड़े पर उसके अंगूठे का निशान लिया था। अ०सा०-3 निश्चित रूप से तहरीर का लेखक है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष के इस गवाह ने भी प्राथमिकी की सामग्री को साबित नहीं किया है और आरोप लगाया है कि यह उनके द्वारा पुलिस निरीक्षक के आदेश के तहत लिखा गया था। उन्होंने अ०सा०-1 के बयान की भी पुष्टि की है कि उन्होंने तहरीर लिखने से पहले या उस समय घायल कृष्णा शर्मा से कोई निर्देश नहीं लिया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि शिकायत उनके द्वारा थाना में लिखी गई थी। अ०सा०-1 ने अ०सा०-3 द्वारा बनाए गए संस्करण का भी समर्थन किया और इस तथ्य की पुष्टि की कि उसने अ०सा०-3 को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया था। अ०सा०-3 ने विशेष रूप से गवाही दी कि यहां तक कि कागज और कलम भी उसे पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रदान की गई थी, हालांकि यह विवादित नहीं है कि लिखित शिकायत उसकी लिखावट में थी। अ०सा०-1 और अ०सा०-3 के बयान के अवलोकन से, यह प्रदर्शित किया गया है कि दोनों गवाहों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके समझौते के अनुसार दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि यह पुलिस के आदेश पर लिखी गई थी और उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज संस्करण नहीं दिया था। नतीजतन, यह अभिलेखों पर स्थापित किया गया है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने पुष्टिकारक और संभावित मूल्य को खो देती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध दस्तावेज प्रतीत होती है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

33. इस संबंध में कानून काफी हद तक व्यवस्थित है और यह एक प्राथमिकी के साक्ष्य मूल्य पर कानूनी स्थिति की गणना करने वाले कुछ फैसलों का उल्लेख करने के लिए उद्देश्यपूर्ण हो सकता है जो सूचनाकर्ता के बजाय दागी, पूर्ववर्ती और पुलिस के संस्करण को प्रतिबिंबित करता है। **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनती रामुलु और अन्य 1994 पूरक (1) एस.सी.सी. 590** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"5. अ०सा०-22, सर्किल इंस्पेक्टर के साक्ष्य के अनुसार, उन्हें पुलिस कांस्टेबल संख्या-1278 से घटना की जानकारी मिली थी, जो 'बंदोबस्त' ड्यूटी पर था। प्राप्त करने पर। घटना की सूचना देते हुए अ०सा०-22 घटना के गांव के लिए रवाना हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच करने के लिए गांव जाने से पहले, अ०सा०-22 ने अपने



साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसने दैनिक डायरी में कोई प्रविष्टि नहीं की थी या रोज़नामचा में उस जानकारी के बारे में अभिलेखों किया था जो कांस्टेबल 1278 द्वारा उसे दी गई थी, जो उसे जानकारी देने वाला पहला व्यक्ति था, जिसके आधार पर वह मौके पर गया था और जांच हाथ में ले ली थी। जब अ०सा०-1 गांव में लिखित शिकायत के साथ थाना से लौटा तो ही इसे सर्किल इंस्पेक्टर, अ०सा०-22 द्वारा दोपहर लगभग 12.30 बजे मामले की विवेचना के दौरान प्राथमिकी, एक्स. पी-1 के रूप में दर्ज किया गया था। हमारी राय में, शिकायत, प्रदर्श P-1, को मामले में प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह निश्चित रूप से एक मामले की विवेचना के दौरान दिया गया एक बयान होगा और धारा 162, द.प्र.स. द्वारा मारा जाएगा। तथ्य की बात के रूप में, उच्च न्यायालय ने इस आशय का एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रदर्श P-1 को नरसरावपेट में तैयार नहीं किया गया था और इसे "उचित विचार-विमर्श के बाद पामिदीपाडु में ही अस्तित्व में लाया गया था"। एक बार जब हम पाते हैं कि विवेचनाधिकारी जानबूझकर प्रकृति के संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा है, जैसा कि इस मामले में है, और उचित विचार-विमर्श, परामर्श और चर्चा के बाद मौके पर पहुंचने के बाद पहली सूचना रिपोर्ट तैयार की थी, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि जांच दागी है और यह होगा, इसलिए, इस तरह की दागी जांच पर भरोसा करना असुरक्षित है, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कि पुलिस अधिकारी सबूत गढ़ने और झूठे सुराग बनाने के लिए कहां झुक गया होगा। हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि गवाह अ०सा०-3 और अ०सा०-4, मृतक के बच्चे या अ०सा०-1 और अ०सा०-2 के बच्चे जो मृतक से भी संबंधित हैं, अपने आप में उनकी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह कि साक्ष्य का संबंध या पक्षपातपूर्ण प्रकृति केवल न्यायालय को सबूतों की अधिक सावधानी से जांच करने के लिए सतर्क करती है, हम पाते हैं कि इस मामले में जब जांच की प्रामाणिकता पर सफलतापूर्वक हमला किया गया है, तो इन गवाहों की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा, या तो एक ठोस प्रकृति के मजबूत पुष्टिकारक सबूतों के अभाव में, जो इस मामले में अनुपस्थित पाया गया है। (महत्व सन्निविष्ट)

34. राम सुत यादव उर्फ लवकुश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 एस.सी.सी.

ऑनलाइन इला 450 के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"श्री वीरेश मिश्रा का एक और तर्क यह है कि प्राथमिकी को शिकायतकर्ता धरास यादव के आदेश पर साबित नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अकेले इसी आधार पर जमीन पर आता है। हमें इस सबमिशन में पर्याप्त योग्यता मिलती है। शिकायतकर्ता धरास यादव (अ०सा०-4) ने कहा कि प्राथमिकी उसके द्वारा दर्ज नहीं की गई थी और इस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि वह घटना के समय मौजूद नहीं थे। एफ.आई.आर. मुंतजीर अहमद (अ०सा०-3) के लेखक ने भी मुकर लिया और कहा कि एफ.आई.आर. थानाध्यक्ष श्री मृत्युंजय मिश्रा के आदेश पर उनके द्वारा थाना मधुबन में लिखा गया था। विद्वान अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई जिसमें उन्होंने कहा कि वह शाम 7: 30 - 8: 00 बजे तक एक औषधालय में काम करते हैं। जब वह डिस्पेंसरी से घर लौटा तो उसे पता चला कि धरास यादव के घर पर फायरिंग हुई है। वह मौके पर गया और उसके बाद थाना गया जहां उसने घायल जयराम और जय किशन को पाया। इस गवाह के बयान से यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी गांव में नहीं लिखा गया था, बल्कि मुंतजीर अहमद (अ०सा०-3) द्वारा थाना में कथित तौर पर थानाध्यक्ष के आदेश पर लिखा गया था। शिकायतकर्ता धरास यादव ने प्राथमिकी पर अपने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार किया है। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि प्राथमिकी पर हस्ताक्षर धरास यादव के हैं। यहां तक कि जयराम (अ०सा०-5) से भी इस बिंदु पर अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। उन्हें अपने भाई धरास यादव के हस्ताक्षर की पहचान करने के लिए कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह दिखाने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं है कि प्राथमिकी पर धरास यादव के हस्ताक्षर हैं या शिकायतकर्ता के आदेश पर लिखा गया था। दूसरी ओर, मुंतजीर अहमद (अ०सा०-3) के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्राथमिकी थानाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा के आदेश पर लिखा गया था, जिनकी अपीलकर्ता युधिष्ठिर उर्फ धर्म राज यादव, राम सुत यादव उर्फ लवकुश यादव, उनके पिता राम नरेश और अपीलकर्ता राम अवतार यादव के साथ दुश्मनी थी। इस संभावना



से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं का नाम थानाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा और एसआई वासुदेव सिंह के कहने पर प्राथमिकी में रखा गया था। चूंकि प्राथमिकी कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ है और यह एक संदिग्ध दस्तावेज है, इसलिए पूरा मामला जमीन पर उतर जाता है और उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(महत्व सन्निविष्ट)

35. इस समय यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं होना चाहिए कि अ०सा०-4, कांस्टेबल विश्वनाथ के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने अ०सा०-3 द्वारा लिखित और प्रस्तुत तहरीर के आधार पर धारा 460 भ०द०वि० के तहत शुरू में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी प्रदर्श क-2 को 25.07.2004 को सुबह 3:15 बजे दर्ज किया गया है और इसे सुबह 3:15 बजे रोज़नामचा में प्रदर्श क-3 के माध्यम से दर्ज किया गया था, और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद जांच की गई थी। अ०सा०-4 कांस्टेबल विश्वनाथ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण और रोज़नामचा में इसकी प्रविष्टि को साबित किया है। ततस्य विपरीत, अ०सा०-3 ने गवाही दी कि तहरीर उसके द्वारा सुबह 8-8:30 बजे के बीच पुलिस निरीक्षक के आदेश के तहत लिखी गई थी, जो स्पष्ट रूप से विपरीत है और अ०सा०-4 के साक्ष्य के भौतिक विरोधाभास में है, जिसके अनुसार पहली जानकारी सुबह 3:15 बजे दर्ज की गई थी। चूंकि तहरीर की प्रस्तुति के संबंध में अ०सा०-3 के साक्ष्य के विपरीत है, इसलिए इसे सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सुबह 3:15 बजे दर्ज की गई थी।

36. एक और स्पष्ट तथ्य जो अभिलेखों से उभरने वाली प्राथमिकी दर्ज करने के समय के बारे में संदेह का समर्थन करता है, वह यह है कि घायल अ०सा०-1 को पुलिस द्वारा ही सुबह 4:40 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन घायल कृष्णा शर्मा से संबंधित मेडिकल कागजात में प्राथमिकी दर्ज करने का कोई उल्लेख नहीं है। अगर प्राथमिकी तड़के 3:15 बजे दर्ज की जाती और प्राथमिकी के अनुपालन में पुलिस मौके पर पहुंचती और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाती, तो घायलों के मेडिकल पेपर्स में प्राथमिकी दर्ज हो जाती। इसके अलावा, अ०सा०-4 ने स्वीकार किया है कि घटना की तारीख को किसी अन्य मामले की रोज़नामचा में कोई प्रविष्टि नहीं थी। यदि प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख को कुछ अन्य मामलों की रोज़नामचा में प्रविष्टियां मिल जातीं, तो यह स्वीकार किया जा सकता था कि रिपोर्ट 3:15 बजे दर्ज की गई थी। हालांकि, माना जाता है कि कोई प्रविष्टि नहीं मिली है, इसलिए, समय से पहले प्राथमिकी के बारे में बचाव



पक्ष के तर्कों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और अभिलेखों में हेरफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्थापित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.07.2004 को दिनांक 25.07.2004 को पूर्वाह्न 3:15 बजे पंजीकृत नहीं हुई है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

37. मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 5 एस.सी.सी. 188 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"12. एक आपराधिक मामले में और विशेष रूप से एक हत्या के मामले में प्राथमिकी मुकदमे में नेतृत्व किए गए सबूतों की मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सबूत का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है। प्राथमिकी को शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उस परिस्थिति के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा खेले गए हिस्से, इस्तेमाल किए गए हथियार, यदि कोई हो, के साथ-साथ चश्मदीद गवाहों के नाम, यदि कोई हो, शामिल हैं। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के परिणामस्वरूप अक्सर अलंकरण होता है, जो बाद के विचार का प्राणी है। देरी के कारण, प्राथमिकी न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि रंगीन संस्करण या अतिरंजित कहानी के परिचय में भी खतरा पैदा हो जाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राथमिकी उस समय दर्ज की गई थी जब इसे दर्ज किया गया था, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जांचों की तलाश करती हैं। जांचों में से एक प्राथमिकी की प्रति की प्राप्ति है, जिसे स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा हत्या के मामले में एक विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देर से प्राप्त होती है, तो यह एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि प्राथमिकी उस समय दर्ज नहीं की गई थी, जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी की प्रति भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है। दूसरा बाहरी जांच भी उतना ही महत्वपूर्ण है शव के साथ प्राथमिकी की कॉपी भेजना और जांच रिपोर्ट में उसका संदर्भ। भले ही धारा 174 द०प्र०स० के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट का उद्देश्य एक वैधानिक कार्य करना है, अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करना है, लेकिन प्राथमिकी का विवरण और जांच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों का सार रिपोर्ट में परिलक्षित



होता है। उन विवरणों की अनुपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि अभियोजन की कहानी अभी भी भ्रूण की स्थिति में थी और इसे कोई आकार नहीं दिया गया था और प्राथमिकी को बाद में उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज किया गया था और फिर इसे तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी का रंग देने के लिए समय दिया गया था। हमारी राय में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्राथमिकी ने अपना मूल्य और प्रामाणिकता खो दी है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह 'समय से पहले किया गया है' और अ०सा०-8 द्वारा मौके पर जांच की कार्यवाही समाप्त होने तक दर्ज नहीं किया गया था। (महत्व सन्निविष्ट)

38. मो. मुस्लिम बनाम उत्तर प्रदेश आपराधिक अपील संख्या 1089 वर्ष 2011 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी की साक्ष्य भूमिका के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"चेक प्राथमिकी रिपोर्ट लगभग 4 दिनों की देरी से 08.08.1995 को न्यायालय को भेजी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि एक आपराधिक मामले में और विशेष रूप से एक हत्या के मामले में प्राथमिकी एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सबूत है, विशेष रूप से मुकदमे में पेश किए गए सबूतों की मूल्यांकन करने के उद्देश्य से। यही कारण है कि प्राथमिकी में कमजोरियां, यदि कोई हों, इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती हैं। ऐसे मामलों में प्राथमिकी का साक्ष्य मूल्य भी कम हो सकता है। महाराज सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में यह राय दी गई है कि कमजोरियों के कारण प्राथमिकी के इस तरह के एंटे टाइम का प्रमाण अपना साक्ष्य मूल्य खो देता है। इस प्रकार, यह आरोपी को संदेह का लाभ देने का अधिकार देता है। (महत्व सन्निविष्ट)

39. जहां तक अपराध करने में अभियुक्त की मिलीभगत का संबंध है, अपीलकर्ताओं के अपराध और दोषसिद्धि को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित दो परिस्थितियों की श्रृंखला पर अवलंबन किया:

- i. अ०सा०-1 और अ०सा०-2 के चक्षुक साक्ष्य, जिन्होंने अपराध करते समय कथित तौर पर आरोपी की पहचान की



ii. आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान और उसके परिणामस्वरूप बरामदगी।

40. पहली परिस्थिति के निर्धारण के लिए, हमें इन दो स्टार गवाहों की गवाही के माध्यम से लिया गया है। अंसा०-7 के दूसरे विवेचनाधिकारी ने गवाही दी कि आरोपी कल्लू और छतरपाल की मिलीभगत शुरू में क-म शैल के बयान में सामने आई, जिसे उसके द्वारा 27.04.2004 को दर्ज किया गया था और बाद में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 02.08.2004 को दर्ज कृष्ण शर्मा के बयान में दर्ज किया गया था। उपर्युक्त के आधार पर दोनों अभियुक्तों को 07-08-2004 को और आरोपी खुशी राम को 09-08-2004 को गिरफ्तार किया गया था। विवेचनाधिकारी अंसा०-7 के अनुसार, आरोपी की कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, क्योंकि आरोपियों का नाम पहले से ही घायल कृष्णा शर्मा और चश्मदीद गवाह कुमारी शैल अंसा०-2 द्वारा रखा गया था। यहां यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अंसा०-1 और अंसा०-2 के चक्षुक साक्ष्य द्वारा अपीलकर्ताओं की भागीदारी को सेवा में बताया गया है।

41. निर्विवाद रूप से, अंसा०-1 कृष्णा शर्मा एक घायल और दुर्भाग्यपूर्ण रात को किए गए पूरे प्रकरण के चश्मदीद गवाह हैं। कानून स्थापित है कि एक घायल गवाह के साक्ष्य को हमेशा एक साधारण गवाह की तुलना में उच्च आसन पर रखा जाता है और एक घायल गवाह के साक्ष्य को आमतौर पर विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ऐसे गवाह द्वारा लगी चोट का तात्पर्य मौके पर उसकी उपस्थिति से होता है। हालांकि, ऐसे गवाह की विश्वसनीयता हमलावरों को देखने के अवसर, बिजली की स्थिति यदि रात की घटना है, गवाहों की मनःस्थिति आदि पर निर्भर करती है। न्यायालय को यह भी निर्धारित करना होगा कि क्या घायल गवाह अंधेरे में आरोपी की पहचान करने की स्थिति में था, विशेष रूप से जब वह खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ अचानक हमले में और चारों ओर भय और सदमे के माहौल में घायल हो गई थी।

42. **जोधन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2015) 11 एस.सी.सी. 52** के मामले में संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घायल गवाह की गवाही के महत्व के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"29. कानूनी सिद्धांतों के पूर्वोक्त सारांश से, यह संदेह से परे है कि घायल गवाह की गवाही का अपना महत्व है और उस पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए मजबूत आधार न हों। जैसा कि कहा गया है, घायल गवाह को कानून में विशेष दर्जा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया गया है और उसके द्वारा लगी चोट घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी है। इस प्रकार माना जाता है, हम वास्तव में अपीलकर्ता के अधिवक्ता की प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते हैं कि घायल गवाहों के साक्ष्य को विचारण न्यायाधीश द्वारा अविश्वसनीय माना जा रहा है। (महत्व सन्निविष्ट)

43. बोल्लावरम पेड्डा नरसी रेड्डी बनाम के मामले में। आन्ध्र प्रदेश राज्य 1991 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 183 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रचलित प्रकाश की स्थिति के महत्व पर जोर दिया जहां घटना रात के दौरान होती है और अभियुक्त व्यक्तियों को गवाहों के लिए अज्ञात होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"9. प्रस्तुत मामले में, अपीलकर्ता स्वीकार किए गए व्यक्ति हैं जिनके साथ दो गवाहों का कोई पूर्व परिचय नहीं था। घटना एक अंधेरी रात में हुई। जब अपराध अंधेरे के घंटों के दौरान किया गया था और हमलावर गवाहों के लिए पूरी तरह से अजनबी होते हैं, तो आरोपी व्यक्तियों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रचलित प्रकाश महत्वपूर्ण महत्व का विषय है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गवाहों द्वारा उनकी पहचान करने की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक पर हमला अचानक और एक साथ हुआ और हमलावर कुछ ही समय में भाग गए। अंसा०-1 और 2 दोनों ने गवाही दी थी कि वे विस्फोट से आकर्षित हुए थे और जब वे वापस मुड़े, तो हमलावरों ने मृतक को घेर लिया और चाकू से वार किया। अंसा०-1 को एक तरफ धकेल दिया गया। वह ट्रांसफार्मर के कंटीले तार की बाड़ पर गिर गया, खरोंच आ गई। उसकी धोती तार से चिपक गई। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और पूरी तरह से असमंजस में थाना की ओर भागा। उनका बयान प्रदर्श P-1 यह खुलासा नहीं करता है कि अंसा०-2 उनके साथ था, हालांकि अंसा०-s 1 और 2 ने न्यायालय के समक्ष कहा कि वे एक साथ गए थे। मृतक के साथियों के बिखरे होने और अलग-अलग दिशाओं में चले जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि पूर्व पी-1 बयान में भी अंसा०-1 ने जो कहा वह यह है कि छह व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया; वे ग्रामीण थे; उन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। एक की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और उसका रंग सांवला था, दूसरा 30 वर्ष का दुबला था और दूसरा भी दुबला व्यक्ति था। हमलावरों को अचानक देखने पर गवाह की यह अस्पष्ट धारणा हो सकती है। हालांकि यह सबूत में नहीं है कि



अ०सा०-1 द्वारा दिया गया विवरण अपीलकर्ताओं में से किसी एक के विवरण के साथ फिट बैठता है। जब मजिस्ट्रेटों ने गवाहों के बयान दर्ज किए, तो वे हमलावरों में से किसी एक की कोई विशिष्ट विशेषता नहीं दे सके। पूरा मामला अपीलकर्ताओं की पहचान पर निर्भर करता है और पहचान पूरी तरह से परीक्षण पहचान परेड पर आधारित होती है।
(महत्व सन्निविष्ट)

44. अब, इस न्यायालय को अ०सा०-1 और अ०सा०-2 द्वारा पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण करना होगा, जिन्होंने विवेचना के दौरान अपने बयान दर्ज कराए थे कि वे घटनास्थल पर केवल आरोपी कल्लू और छत्र पाल की पहचान कर सकते थे, अन्य की नहीं। ततस्य विपरीत, उन्होंने न्यायालय के समक्ष गवाही दी कि उन्होंने बल्ब और टॉर्च की रोशनी में घटनास्थल पर ही कल्लू, छत्र पाल, खुशी राम और मन्नी लाल नाम के आरोपियों की पहचान की। इसलिए दोनों ने अपने साक्ष्य में आरोपी मन्नीलाल और खुशी राम से जुड़ा एक नया तथ्य जोड़ा, जबकि विवेचना के दौरान यह तथ्य पहले पुलिस को नहीं बताया गया था। बिना किसी स्पष्टीकरण के, किसी के पहले के बयान के विपरीत, बयान को एक गंभीर असंगति और सुधार के रूप में माना जाएगा, और गवाहों की बेहतर गवाही बदनाम साक्ष्य की श्रेणी में आएगी। एक और परिस्थिति जिसने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वह यह है कि विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपी मणिलाल को अपराध में शामिल नहीं पाया गया था, विवेचना के दौरान और आरोपी कल्लू, छत्र पाल और खुशी राम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और यह केवल अ०सा०-1 की मुख्य परीक्षा में है, कि आरोपी मणिलाल का नाम सामने आया था और अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर, उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए धारा 319 द०प्र०स० के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने तलब किया था। फिर से, अ०सा०-7 के विवेचनाधिकारी ने कहा कि उन्होंने आरोपी कल्लू और छत्र पाल द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर ही आरोपी खुशी राम की मिलीभगत पाई और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने खुलासा बयान दिया जिससे अ०सा०-1 के घर पर की गई डकैती से संबंधित आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी हुई। हालांकि, मुकदमे के दौरान दोनों तथ्यात्मक गवाहों ने कहा कि आरोपी खुशी राम और मुन्नीलाल भी आरोपी कल्लू और छत्रपाल के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। इसके अलावा, अ०सा०-1 ने गवाही दी है कि संबंधित पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी, और इसलिए उसने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजे थे। हालांकि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं



है कि उनके द्वारा कभी भी उच्च अधिकारियों को कथित अभ्यावेदन भेजा गया था और कभी कार्रवाई की गई है। इसलिए, मुकदमे के चरण में अंसा०-1 द्वारा कथित रूप से उच्च अधिकारियों को भेजे गए प्रतिनिधित्व की फोटो प्रतियों को अभिलेखों पर रखने से कोई संभावित मूल्य नहीं हो सकता है।

45. एक अन्य कारक वह है प्रासंगिक समय पर घटना के स्थान के आसपास दृश्यता का कारक, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी कल्लू और छत्रपाल को घायल कृष्णा शर्मा के पति और बेटे ने कथित अपराधियों का विरोध करते समय पहचान लिया था। यह कहा गया है कि पीड़ित शिव कुमार और वेद प्रकाश ने अपराध के दौरान आरोपी कल्लू और छत्रपाल का नाम लिया और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अंसा०-1 ने गवाही दी कि शोर सुनकर, वह जाग गई और देखा कि कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसकी बहू कल्पना की चूड़ियां छीन ली थीं और उसके बेटे और पति से आरोपी कल्लू और छत्रपाल के नाम सुने थे। उसने पड़ोस के घरों और आरोपियों की टॉर्च से आ रही रोशनी में भी आरोपियों की पहचान की। अंसा०-2 ने अंसा०-1 के संस्करण की भी पुष्टि की। यहां दी गई परिस्थितियों में, यदि गवाहों ने कहा कि अभियुक्तों की पहचान उनके द्वारा आस-पास के घरों से आने वाली रोशनी में की गई थी, तो न्यायालय को इस तथ्य की जांच करनी होगी कि क्या पीड़ित और घायल स्थिति में थे और उनके पास आरोपी को पहचानने का कोई अवसर था। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या आस-पास के घरों में रोशनी थी, और यदि हां, तो क्या वह प्रकाश, अचानक और हिंसक हमले के बावजूद, पीड़ित के लिए अभियुक्त की पहचान करने के लिए पर्याप्त था?

इस संबंध में, जब अंसा०-1 को जिरह में रखा गया, तो उसने स्वीकार किया कि घटना के लगभग एक वर्ष से उसके घर में बिजली का कनेक्शन था। उसके घर के बगल में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट के स्रोत के बारे में जांच करने पर, अंसा०-1 ने स्वीकार किया कि घटना से लगभग 15 दिनों पहले, उसके घर के बाहर बिजली के खंभे पर लगा बल्ब काम नहीं कर रहा था और पड़ोसी के अनुरोध पर बंद कर दिया गया था। इसलिए, उसके प्रवेश से ही यह स्पष्ट है कि अंसा०-1 के घर के सामने स्थापित स्ट्रीट लाइट घटना की रात के दौरान काम करने की स्थिति में नहीं थी। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि गवाहों ने अपनी छत से आने वाले प्रकाश में अभियुक्तों की पहचान की। यह भी संकेत नहीं दिया गया है कि छत पर प्रकाश का कोई अन्य स्रोत था।



ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिलेखों पर स्थापित किया गया है कि उनके घर की छत पर स्ट्रीट लाइट से भी किसी रोशनी का कोई सवाल ही नहीं था।

46. इस संबंध में, थानेदार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002) 1 एस.सी.सी. 487, के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेहराज (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उन मामलों में प्रकाश के स्रोत को स्थापित करने के महत्व के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, जहां कथित घटना रात में अज्ञात व्यक्तियों से जुड़ी होती है:

"8. हालांकि, पहचान के पहलू पर, उच्च न्यायालय को **नथुनी यादव बनाम बिहार राज्य (1998 (9) एस.सी.सी. 238)** के आधार पर टिप्पणी करने में उचित ठहराया जा सकता है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। नथुनी यादव के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने बताया कि कुछ परिस्थितियों में, चांदनी या कृत्रिम प्रकाश की कमी हमलावरों की पहचान को रोकती नहीं है। न्यायमूर्ति थॉमस ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा: -

यह मानते हुए भी कि तब चांदनी नहीं थी, हमें स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा। जिस निकटता पर हमलावरों ने घायलों का सामना किया होगा, सितारों की चमक से वहां कुछ प्रकाश पहुंचने की संभावना, और यह तथ्य कि हत्या छत रहित छत पर की गई थी, यह देखते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं कि क्या पीड़ितों के पास हमलावरों की सही पहचान करने के लिए पर्याप्त दृश्यता हो सकती थी। उन कारकों के अलावा, हमें आगे के तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हमलावर त्रासदी से ग्रस्त घर के निवासियों के लिए अजनबी नहीं थे, प्रत्यक्षदर्शी हत्यारों में से प्रत्येक की शारीरिक बनावट से अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए, हम यह मानने के लिए राजी नहीं हैं कि पीड़ितों के लिए हमलावरों को देखना संभव नहीं होगा या उनकी गलत पहचान करने की संभावना थी। हम इस तथ्य को ध्यान में रख रहे हैं कि हमलावरों के पास भी इतनी रोशनी थी कि वे उन पीड़ितों की पहचान कर सकें जिन्हें उन्होंने बिना किसी गलती के छत पर सो रहे लोगों में से निशाना बनाया था।

9. जबकि प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त-अपीलकर्ता की पहचान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी अजनबी नहीं



था और घटना एक खुली जगह पर थी, एक और कारक है जो पहचान के मामले में कुछ कठिनाई पैदा करता है। अंसा०-6 उस स्थान से थोड़ी दूरी पर एक खाट पर सो रहा था जहां पीड़ित सो रहा था। अंसा०-6 ने कहा कि अपीलकर्ता सहित पांच व्यक्तियों ने उनके बेटे को घेर लिया और दो आरोपी उसकी खाट के सामने खड़े थे। इस स्थिति में, यह मानते हुए कि खुले आसमान से हल्की रोशनी निकल रही थी, क्या अंसा०-6 के लिए अपीलकर्ता को राइफल से गोली चलाते हुए देखना संभव होगा? संभावना दूर लगती है। किसी भी दर पर, अंसा०-6 द्वारा पहचान के बिंदु पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटने से पहले इस पहलू को उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। (महत्व सन्निविष्ट)

47. अब अगला मुद्दा यह है कि क्या आस-पास में घर थे, और यदि हां, तो क्या उन घरों में बिजली के कनेक्शन थे, और अंत में, क्या घटना के समय, उन घरों से पर्याप्त रोशनी आ रही थी ताकि गवाह अभियुक्तों की पहचान कर सकें? अपने पक्ष में संभावनाओं का पता लगाने के लिए, आरोपी द्वारा जिरह की गई, जिसमें अंसा०-1 ने स्वीकार किया कि उसके घर के पूर्व या पश्चिम की ओर कोई घर नहीं था और घर के उत्तरी हिस्से की ओर एक स्कूल निर्माणाधीन था। आगे कहा गया है कि रिक्शा कंपनी है जिसकी 2-3 फीट ऊंची दीवारें हैं, जो उसके घर से सटी हुई हैं। गवाह ने आगे स्वीकार किया कि आसपास के क्षेत्र में कोई घर नहीं थे, बल्कि घर कुछ दूरी पर थे। यहां तक कि अपराध के तुरंत बाद विवेचनाधिकारी द्वारा तैयार की गई नक्शा नज़री प्रदर्शक-7 ने भी आस-पास के किसी भी घर का प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि, यह सच है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अकेले अंसा०-1 का वहां एक घर था। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आस-पास अन्य घर थे, जैसा कि अंसा०-1 ने खुद स्वीकार किया था, लेकिन यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कोई घर इतना करीब था कि घर से रोशनी आ रही थी और उस प्रकाश में आरोपियों की पहचान की गई थी। अभियोजन पक्ष का यह भी कोई विशिष्ट संस्करण नहीं है कि किस पड़ोसी के घर से रोशनी आ रही थी, जिससे आरोपियों की पहचान की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, यह साबित नहीं होता है कि आस-पास कोई घर थे या उन घरों पर कोई बिजली की रोशनी उपलब्ध थी। इसलिए, पड़ोसियों के घरों से आने वाले प्रकाश में अभियुक्तों की पहचान करने के अंसा०-1 और अंसा०-2 के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक इस दावे का सवाल है कि आरोपी द्वारा चालू



टॉर्च की रोशनी में आरोपियों की पहचान की गई थी, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि अचानक हमले और रक्तपात की स्थिति में, गवाह के लिए आरोपी की पहचान करना स्वाभाविक नहीं लगता है।

48. जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है, यह दिखाने के लिए कोई आधार नहीं मिला है कि घटना की रात आसपास के क्षेत्र में प्रकाश का कोई स्रोत था। इस मोड़ पर, यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियां या संभावना मौजूद है जिसमें अभियुक्तों की पहचान उनके शरीर के विवरण, चाल आदि से की गई थी। अंसा०-1 और अंसा०-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि आरोपी मन्नीलाल और कल्लू उनके दूर के रिश्तेदार होने के कारण जानते थे और वे दोनों अपने घर से सटे एक रिक्शा कंपनी का संचालन कर रहे थे। दोनों तथ्यात्मक गवाहों ने कहा कि वे आरोपी छत्रपाल और खुशी राम को तब से जानते थे जब वे अपने घर के बगल में खुली रिक्शा कंपनी में रिक्शा चलाते थे। उन्होंने विशेष रूप से गवाही दी कि ऊपर नामित अभियुक्तों ने अपराध किया और अपराध करने के दौरान और पहचान होने पर, आरोपी छत्रपाल और कल्लू ने चिल्लाया कि उनकी पहचान कर ली गई है और इस प्रकार, परिवार के सभी सदस्यों को खत्म करने के लिए चिल्लाया। इस प्रकार, गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऊपर नामित अभियुक्त ने अपराध किया है और उन्होंने मौके पर ही आरोपी की पहचान कर ली। जहां तक अंसा०-1 द्वारा अपीलकर्ताओं की पहचान किए जाने और अपीलकर्ताओं के साथ उसके संबंधों का सवाल है, जब उसे इस तथ्य पर जिरह में रखा गया था, तो उसके द्वारा यह कहा गया था कि न तो उसका आरोपी मन्नीलाल और कल्लू के साथ कोई संबंध था, न ही वह कभी उनके घर या गांव गई थी। उसने आगे स्वीकार किया कि वह आरोपी मन्नीलाल और कल्लू के साथ बात नहीं कर रही थी, और दोनों में से कोई भी कभी उसके घर नहीं गया था। रिक्शा कंपनी के प्रबंधन के बारे में पूछे जाने पर उसने जवाब दिया कि आरोपी कल्लू रिक्शा कंपनी चला रहा था, जबकि आरोपी मन्नीलाल रेलवे में सेवा कर रहा था। जिरह से, यह प्रदर्शित किया गया है कि आरोपी मन्नीलाल और कल्लू के दूर के रिश्तेदार होने के अंसा०-1 का दावा उसके अपने बयान से खंडन करता है, इसलिए, इस हद तक अंसा०-1 के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

49. एक और दिलचस्प तथ्य जो अंसा०-1 और अंसा०-2 के साक्ष्य से उभरा है, वह यह है कि आरोपी मन्नी लाल और कल्लू ने घटना के समय अपने चेहरे ढके हुए थे, जबकि आरोपी छत्रा पाल ने मंकी कैप पहनी हुई थी। यह एक विवेकपूर्ण व्यक्ति की कल्पना से परे है कि प्रकाश के



अभाव में ढके हुए चेहरे वाले व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है और विशेष रूप से जब वह परिचित नहीं है। विवेचनाधिकारी अ०सा०-7 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद आरोपी की पहचान परीक्षण परेड नहीं की। विवेचनाधिकारी अ०सा०-7 द्वारा परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं करने का कारण यह बताया गया था कि विवेचना के दौरान आरोपियों के नाम सामने आए थे। एक बार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामले की प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद, चाहे जो भी स्थिति हो, विवेचनाधिकारी की ओर से यह अनिवार्य है कि वह किसी मामले में शामिल पाए गए अभियुक्त की परीक्षण पहचान परेड आयोजित करे। परीक्षण पहचान परेड का उद्देश्य गवाहों की सत्यता की जांच करना और आगे उस अभियुक्त की पहचान करने का अवसर प्राप्त करना है जिसे गवाह घटना के समय देखे जाने का दावा करता है। परीक्षण पहचान परेड में पहचान बाद में न्यायालय में किए गए अभियुक्त की पहचान का समर्थन करने के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में कार्य करती है। प्रस्तुत मामले में, माना जाता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी पहले एक-दूसरे को जानते थे। जब अभियुक्तों ने अपने चेहरे को दबा लिया था और घटना के स्थान पर प्रकाश का स्रोत अनुपस्थित था और घटना रात के अंधेरे में हुई थी, तो विवेचना के दौरान परीक्षण पहचान परेड की अनुपस्थिति और न्यायालय में आरोपी की पहचान करने से सबूत असुरक्षित हो जाएंगे।

50. परीक्षण पहचान परेड उन मामलों में अधिक महत्व रखती है जहां आरोपी और गवाह एक-दूसरे के लिए अज्ञात हैं या एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित नहीं हैं और जहां कथित घटना रात के अंधेरे में होती है। **वाहिद बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार 2025 आई.एन.एस.सी. 145** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं,

"22. आम तौर पर, जहां अभियुक्त व्यक्ति अज्ञात होते हैं और प्राथमिकी में उनका नाम नहीं होता है, यदि अभियोजन पक्ष के मामले में जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो न्यायालय को अन्य सबूतों के साथ सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और निष्पक्ष रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अन्य सभी परिस्थितियां उचित संदेह से परे साबित हुई थीं। इस आलोक में अब हम अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करेंगे। माना जाता है कि यह रात की घटना का मामला है। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना



के सात चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन केवल तीन (यानी, अ०सा०-1, अ०सा०-5 और अ०सा०-6) ने न्यायालय में अभियुक्तों की पहचान की। शेष चार में से चालक सहित तीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने उस रात यात्रियों को लूटा था। चौथे ने कहा कि बहुत अंधेरा था, इसलिए वह पहचान नहीं पा रहा है। अ०सा०-1, जिसके कहने पर आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी कथित तौर पर की गई थी, जिरह के दौरान कहा गया कि उसने आरोपी व्यक्तियों को पहले घटना की तारीख को और दूसरी बार मामले में निर्धारित तारीख को देखा था। माना जाता है कि कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी और अ०सा०-1 का बयान 28.05.2013 को न्यायालय में दर्ज किया गया था, यानी घटना के 16 महीने बाद। ऐसी परिस्थितियों में उनके बयान पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। (महत्व सन्निविष्ट)

51. अ०सा०-1 की जिरह में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुशी राम और छत्रपाल की पहचान परीक्षण परेड जेल में आयोजित की गई थी। हालांकि, विवेचनाधिकारी अ०सा०-7 ने अ०सा०-1 के संस्करण का खंडन करते हुए विशेष रूप से कहा कि अभियुक्त की कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए, परीक्षण पहचान परेड के तथ्य से संबंधित अ०सा०-1 और अ०सा०-7 के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी पाए जाते हैं। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि आरोपी खुशी राम ने संबंधित अपराध में अपनी संलिप्तता की आशंका जताई और संबंधित न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि वह अपनी पहचान परीक्षण परेड आयोजित करे और संबंधित न्यायालय ने विवेचनाधिकारी को आरोपी की पहचान परीक्षण परेड आयोजित करने का निर्देश दिया। तथापि, संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई। अभियोजन पक्ष का मामला है कि शुरुआत में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के नाम सामने आए थे। तत्स्य विपरीत, अ०सा०-1 ने पूरी तरह से अलग बयान देते हुए अपनी गवाही में कहा कि उसने अपराध करने के समय ही आरोपी की पहचान कर ली थी। अ०सा०-1 द्वारा मुख्य परीक्षा में यह नहीं कहा गया है कि विवेचनाधिकारी ने विवेचना के दौरान अपराध के संबंध में अपना बयान दर्ज किया था, बल्कि अपनी जिरह में, उसने कहा कि विवेचना के दौरान उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, अ०सा०-1 के अनुसार,



विवेचना के दौरान उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था। विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज नहीं कराने के संबंध में उसकी स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए, आरोपी की संलिप्तता का तथ्य पहली बार न्यायालय के सामने आया है। विवेचना के दौरान लाए गए तथ्यों की अनदेखी करते हुए पहली बार न्यायालय के समक्ष किसी गवाह द्वारा दिया गया कोई भी बयान न केवल की गई जांच के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है, बल्कि न्यायालय को गवाह की गवाही पर भरोसा न करने का कारण भी प्रदान करता है।

52. अ०सा०-2 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में एक और महत्वपूर्ण तथ्य रखा गया है कि अपराध करने के बाद, आरोपी मौके से भाग गया और उसके बाद वह अपनी बहन के साथ नीचे आई और शोर गुल बजाया। नतीजतन, पड़ोसी मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपी मुन्नीलाल और छत्रपाल को उनकी रिक्शा कंपनी में पकड़ लिया। उसने आरोपी मुन्नीलाल और छत्रपाल की पहचान खून से सने कपड़ों से की। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों को ले गई। जब गवाह को जिरह में रखा गया, तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विवेचना के दौरान उसने विवेचनाधिकारी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बयान, जो पहले के बयान से असंगत है, जो पहली बार दिया गया है, भौतिक चूक और सुधार के दायरे में आएगा और इसलिए इसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अ०सा०-2 ने स्वीकार किया कि डर और सदमे के तहत, उसने कमीशन के समय खुद को बेडशीट के नीचे ढक लिया था। उसने आगे कहा कि वह अपनी दादी और छोटी बहन के साथ नीचे आई और देखा कि आरोपी छत्रपाल और मुन्नीलाल को जनता ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। उसने यह कहना जारी रखा कि घटना के बाद और उसके शोर गुल उठाने पर, कुछ पड़ोसियों ने गोलीबारी की और लोग आसपास इकट्ठा हो गए। माना जाता है कि अपराध के समय अ०सा०-2 दस साल का था, इसलिए, उसके बयान का सावधानी और सतर्कता के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बाल गवाह एक सक्षम गवाह नहीं है और ऐसे गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है, यदि इस तरह के सबूत पूरी तरह से बेदाग और त्रुटिहीन प्रतीत होते हैं। हालांकि, इस मामले में, अ०सा०-2 के बयान में भौतिक विरोधाभास और कमजोरियां हैं, इसलिए, किसी भी पुष्ट सबूत के अभाव में उनके बयान को सुसमाचार की सच्चाई के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, अपराध के समय, उसकी आयु दस वर्ष थी, इसलिए प्रकाश के स्रोत के अभाव में घबराहट के दृश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता



है कि वह आरोपी की पहचान करने में काफी असमर्थ थी। इसलिए, अंधेरे में हुई घटना में और अभियुक्तों के चेहरे को दबा कर रखा गया, फिर भी गवाहों और यहां तक कि मृतक द्वारा पहचाना जाना, जो कथित तौर पर उन्हें नाम से बुलाता था, किसी भी सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के लिए विश्वसनीय नहीं लगता है।

53. इस मामले में निपटा जाने वाली एक और परिस्थिति अ०सा०-3 की गवाही है, जो न केवल मामले का सूचनाकर्ता है, बल्कि घटना के तुरंत बाद घटना के स्थान पर खुद को उपस्थित होने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि शोर सुनकर वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी छत्रपाल और कल्लू को मौके पर इकट्ठा लोगों की हिरासत में पाया। आगे उनके द्वारा कहा गया है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को थाना ले गई और घायलों को अस्पताल ले गई। अब विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि जहां एक सूचनाकर्ता, जिसे विवेचना के दौरान केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन मुकदमे के दौरान घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद होने का दावा करता है, तो ऐसे गवाह के साक्ष्य का संभावित मूल्य क्या होगा? माना जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण और उसकी विवेचना के दौरान, अभिलेखों पर कुछ भी नहीं है कि घटना के बाद सूचनाकर्ता अ०सा०-3 भी मौके पर पहुंचा और न्यायालय के समक्ष यह पहली बार है कि गवाह ने ऐसा कहा है, इसलिए, यह भौतिक सुधार के बराबर है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने का प्रयास किया है। घटना के बाद घटनास्थल पर एक गवाह की उपस्थिति और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेते हुए देखना, एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे सूचनाकर्ता या सामान्य विवेक के किसी भी व्यक्ति द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और यदि तहरीर में ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य गायब है, तो निश्चित रूप से, यह अनुमान लगाया जाएगा कि सूचनाकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा है, इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि अ०सा०-3 के पास मौके पर अपनी उपस्थिति के बारे में विवेचनाधिकारी को बयान देने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे, यदि कोई हो, लेकिन उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने का विकल्प नहीं चुना और पूरे समय चुप रहे। इसलिए, उनकी चुप्पी इस बात की स्वीकृति का संकेत है कि वह घटना के बाद घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए, अ०सा०-3 के लिए आरोपी छत्रपाल और कल्लू की हिरासत का निरीक्षण करने का कोई अवसर नहीं था, जिसमें लोग मौके पर इकट्ठे हुए थे। अदालतों ने लगातार माना है कि अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को



प्रभावित करने वाले सुधार गवाह को अविश्वसनीय बनाते हैं और इस तरह के साक्ष्य को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि अभिलेखों पर भरोसेमंद सामग्री द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

54. जहां न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में चश्मदीद गवाहों द्वारा विरोधाभासी बयान और सुधार किए जाते हैं, ऐसे साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाते हैं और दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकते हैं। एस. गोविंदराजू बनाम माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्णाटक राज्य, (2013) 15 एस.सी.सी. 315 के मामले में प्रस्तर-23 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं

‘यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि सबूतों की मूल्यांकन करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विरोधाभास/चूक इतनी बड़ी थी कि मुकदमे को भौतिक रूप से प्रभावित किया जा सके। मामूली विरोधाभास, विसंगतियों, अलंकरण या तुच्छ मामलों के संबंध में सुधार, जो अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, को सीआरएल के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। A.1736/2018 सी/डब्ल्यू साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करना। विचारण न्यायालय को, उपलब्ध सभी सबूतों को देखने के बाद, गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी चाहिए, और अपीलीय न्यायालय को सामान्य कार्रवाई में, ऐसा करने के लिए उचित कारण प्रदान किए बिना, इसकी समीक्षा करना उचित नहीं होगा। जहां चूक एक विरोधाभास है, एक गवाह की सत्यता के बारे में एक गंभीर संदेह पैदा करती है, और अन्य गवाह भी सबूतों को स्वीकार्य बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष भौतिक सुधार करते हैं, ऐसे सबूतों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां, यदि प्रकृति में मामूली नहीं पाई जाती हैं, तो उनके सबूतों पर अविश्वास करने और उन्हें बदनाम करने का आधार हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, गवाह विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकते हैं और यदि उनके साक्ष्य उपलब्ध अन्य सबूतों के साथ या पहले से दर्ज किए जा चुके बयान के साथ विरोधाभास और विरोधाभास में पाए जाते हैं, तो ऐसे मामले में, यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है। (महत्व सन्निविष्ट)

55. सुनील कुमार शंभूदयाल गुप्ता और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 (13) एस.सी.सी. 657

के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"32. चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां, यदि प्रकृति में मामूली नहीं पाई जाती हैं, तो उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने और उन्हें बदनाम करने का आधार हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, गवाह विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकते हैं और यदि उनके साक्ष्य अन्य साक्ष्यों के साथ या पहले से दर्ज किए गए बयान के साथ विरोधाभास और विरोधाभास में पाए जाते हैं, तो ऐसे मामले में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित कर दिया है। (देखें: **महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 11 एस.सी.सी. 334**)

33. यदि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता या गवाह ने धारा 161 द०प्र०स० के तहत अपने बयान में कुछ तथ्यों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन न्यायालय के समक्ष पहली बार अभियोजन पक्ष के मामले का सामना किया है, तो इस तरह के संस्करण में विश्वसनीयता का अभाव है और इसे खारिज किया जा सकता है। (देखें: **पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम सैत @ कृष्णकुमार, (2008) 15 एस.सी.सी. 440 द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व**)

34. **राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कल्कि और अन्य, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1390** में, इस मुद्दे से निपटते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"8.?. गवाहों के बयानों में हमेशा सामान्य विसंगतियां होती हैं, चाहे वे कितनी भी ईमानदार और सच्ची क्यों न हों। ये विसंगतियां अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियां, घटना के समय सदमे और आतंक जैसे मानसिक स्वभाव के कारण होती हैं, और इसी तरह की भौतिक विसंगतियां वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं।

35. अदालतों को उस श्रेणी को लेबल करना होगा जिससे विसंगति संबंधित है। जबकि सामान्य विसंगतियां किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को खराब नहीं करती हैं, भौतिक विसंगतियां ऐसा करती हैं। (देखें: **सैयद इब्राहिम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 2908; और अरुमुगम बनाम राज्य, ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 331**)

56. अ०सा०-3 ने न्यायालय के समक्ष अपनी दोहरी भूमिका का प्रदर्शन किया है। पहली भूमिका तहरीर के मुंशी के रूप में है और दूसरी भूमिका मौके पर उनका कथित रूप से पहुंचना और जनता के हाथों में अभियुक्तों की हिरासत को देखना है। अपने सबूतों को देखने के बाद, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि न तो वह आरोपी मन्नीलाल को जानता है, न ही वह कभी मन्नी लाल के घर गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्हें रिक्शा कंपनी और उसके मालिक से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और उनकी पूरी जानकारी सुनी-सुनाई बातों के स्रोत पर आधारित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वह पहले आरोपी मन्नीलाल या उनमें से किसी से परिचित नहीं था। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान इस गवाह का बयान दर्ज किया गया था, इसलिए, अपराध करने के तुरंत बाद मौके पर उसकी उपस्थिति के बारे में उसकी गवाही, न्यायालय के समक्ष पहली बार बताई गई थी, सामग्री की चूक, ट्यूटर और सुधार के साथ व्यवहार किया जाएगा और अभियोजन पक्ष के समर्थन में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय के समक्ष दिए गए किसी भी बयान को पहली बार नए भौतिक तथ्यों को पेश करना आरोपी के खिलाफ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, पुलिस के मौके पर पहुंचने और थोड़ी देर बाद आरोपी को थाना ले जाने के बारे में उनका बयान, भौतिक विरोधाभास में है और अ०सा०-7 के सबूतों को खारिज करता है, जिसने आरोपी छत्रपाल और कल्लू को 07.08.2004 को गिरफ्तार किया था। इन दोनों गवाहों के बयान परस्पर विरोधाभासी हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यदि पुलिस और सूचनाकर्ता एक-दूसरे का खंडन करते हैं, तो अभियोजन पक्ष को इसे स्पष्ट करना चाहिए और यदि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय अभियुक्त को लाभ पहुंचाने वाला प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है। घटना से ठीक पहले बूदाबांदी के उसके बयान को देखते हुए भी मौके पर अ०सा०-3 की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है, जिससे नई कहानी सामने आती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि इस मौके के गवाह के साक्ष्य को मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के संस्करण को जानने के बाद सिखाया और विकसित किया गया प्रतीत होता है।

57. **हरबीर सिंह बनाम शीशपाल और अन्य, (2016) 16 एस.सी.सी. 418** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संयोग गवाह के साक्ष्य के मूल्य की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया: -



"23. 'संयोग गवाह' के परिभाषित गुणों को महाजन ने पूरन बनाम के मामले में समझाया था। पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 459 में यह माना गया कि ऐसे गवाहों की आदत होती है कि जब कुछ हो रहा होता है तो वे अचानक घटनास्थल पर आ जाते हैं और फिर उस घटना को देखने के बाद गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें बाद में सबूत देने के लिए बुलाया जाता है।

24. मौसम सिंघा रॉय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2003) 12 एस.सी.सी. 377 में, इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि अंसा०-2 और अंसा०-3 के साक्ष्य में कुछ स्पष्ट विरोधाभासों/चूक और प्राथमिकी में उनके नामों की अनुपस्थिति को नीचे के न्यायालयों द्वारा बहुत हल्के ढंग से खारिज कर दिया गया है। इसी तरह, शंकरलाल बनाम राजस्थान राज्य, (2004) 10 एस.सी.सी. 632, और जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एस.सी.सी. 719, इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी हैं कि एक मौका गवाह का बयान, जिसकी घटना के स्थान पर उपस्थिति संदिग्ध बनी हुई है, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों से हम मानते हैं कि अंसा०-5 और अंसा०-6 संयोग के गवाह थे और उनके बयानों को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

25. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज उपरोक्त और अन्य कारणों के आलोक में, हम मानते हैं कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य सत्य, विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं हैं और इसलिए दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते हैं। घटना के समय घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति अत्यधिक अप्राकृतिक है और साथ ही काफी दूरी से प्रत्येक अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से और सही ढंग से पहचानने की उनकी क्षमता भी संदिग्ध है, खासकर जब घटना के कथित स्थान पर अंधेरा हो, अपने आप में संदिग्ध है।

58. अभियुक्त को हत्या के साथ डकैती के अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई अगली परिस्थिति विवेचनाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान और उसके परिणामस्वरूप, अपराध से संबंधित आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी थी। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की स्वीकार्यता के प्रश्न पर चर्चा करने से पहले, कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा।



59. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 (इसके बाद "अधिनियम वर्ष 1872" के रूप में संदर्भित) में कहा गया है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी के सामने की गई कोई भी स्वीकारोक्ति साबित नहीं की जाएगी। इसी तरह, अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 26 में प्रावधान है कि पुलिस की हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दिया गया स्वीकारोक्ति उसके खिलाफ साबित नहीं की जा सकती है। हालांकि, अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 25 और 26 के पूर्वोक्त नियम के लिए, अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 27 द्वारा इस दृष्टिकोण के आधार पर एक अपवाद बनाया गया है कि वास्तव में, यदि दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तव में कुछ तथ्य की खोज की जाती है, तो कुछ गारंटी दी जाती है जिससे जानकारी सत्य थी और तदनुसार, इसे सुरक्षित रूप से साक्ष्य में देने की अनुमति दी गई थी।

60. अधिनियम की धारा 27 के दायरे और दायरे को पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य बनाम सम्राट, ए.आई.आर. 1947 पीसी 67, जो लोकस क्लासिक्स बन गया है, जिसमें यह माना गया था कि धारा 27, जो कलात्मक रूप से शब्द नहीं है, पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा लगाए गए निषेध के लिए एक अपवाद प्रदान करती है और पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करने में सक्षम बनाती है। इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज को गवाही दी जानी चाहिए और उसके बाद इतनी सारी जानकारी जो इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, साबित की जा सकती है। जैसा कि इस मामले में और उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक निर्णयों में देखा गया है, कानून की सुस्पष्ट स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए दो शर्तें पूर्वापेक्षाएं हैं।

i. जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो तथ्य की खोज का कारण बनी हो।

ii. जानकारी को खोजे गए तथ्य से 'स्पष्ट रूप से' संबंधित होना चाहिए।

61. अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 27 के तहत, केवल इतनी ही जानकारी स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है। अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 27 की प्रयोज्यता का निर्णय लेते समय, न्यायालय को अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 114 के उदाहरणों के तहत अनुमान की प्रकृति को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, न्यायालय एक ऐसे तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जिसके बारे में वह सोचता है कि ऐसा होने की संभावना है, किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य प्रविधि के संबंध में। कानून की उपरोक्त चर्चा की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने प्रकटीकरण बयान दिए हैं और आगे घटना के स्थान का सीमांकन किया है।

62. अंसा०-7 के अनुसार, अभियुक्त छत्रपाल तथा कल्लू द्वारा क्रमशः जगदीश कुमार, रामजी एवं कुमारी शैल की उपस्थिति में प्रकटीकरण कथन किए गए। अभियुक्त छत्रपाल के निशानदेही पर दो सोने के कंगन, एक हाथ घड़ी तथा एक डंडा बरामद किया गया, जबकि अभियुक्त कल्लू के निशानदेही पर बच्चों के प्रयुक्त वस्त्र एवं एक डंडा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में क्रमशः बरामदगी पंचनामा/बरामदगी मेमो प्रदर्श क-8 एवं प्रदर्श क-9 के माध्यम से बरामद किए गए। तत्पश्चात्, अभियुक्त खुशीराम को अंसा०-8 निरीक्षक सूर्यनाथ द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उसके निशानदेही पर दो चाँदी के कंगन बरामद किए गए, जिसकी बरामदगी प्रदर्श क-10 के माध्यम से अभिलिखित की गई। अंततः, अभियुक्त ओमकार को दिनांक 09.06.2005 को अंसा०-6 निरीक्षक देवेन्द्र मिश्रा द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर उसके बताने पर एक जोड़ी चाँदी की पायलें बरामद की गईं, जिसकी बरामदगी प्रदर्श क-6 के माध्यम से दर्शाई गई। स्वीकार्यतः, अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किए गए प्रकटीकरण कथनों का कोई पृथक ज्ञापन किसी भी विवेचक द्वारा तैयार नहीं किया गया। न ही कथित बरामदगी तथा बरामदगी ज्ञापनों के तैयार किए जाने की विधिवत् सिद्धि विचारण के दौरान की गई। इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष ने बरामदगी ज्ञापनों के स्वतंत्र साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने का भी पालन नहीं किया। अंसा०-1 एवं अंसा०-2, जिनकी उपस्थिति में कथित वस्तुओं की बरामदगी एवं पहचान किया जाना बताया गया था, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो उक्त वस्तुएँ अभियुक्तों के निशानदेही पर बरामद की गई थीं और न ही उन्हें पहचान हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अतः परिस्थितियों की सम्पूर्ण श्रृंखला स्वयं यह इंगित करती है कि कथित बरामदगी को अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

63. **सुब्रमण्य बनाम के मामले में। कर्नाटक राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1400,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर संख्या-84 में कहा कि यदि अभियुक्त, हिरासत में रहते हुए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनी मर्जी और इच्छा से एक बयान देता है कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार छिपाया था, तो विवेचनाधिकारी को सबसे पहले दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए, और उनकी उपस्थिति में, अभियुक्त को एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए कि क्या वह उस स्थान को इंगित करना चाहता है जहां उसने अपराध के हथियार को छिपाया है, आदि; जहां अभियुक्त, हिरासत में रहते हुए, दो स्वतंत्र गवाहों के सामने ऐसा बयान देता है, तो अभियुक्त द्वारा बोले गए सटीक बयान या यूं कहें कि सटीक शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जिसे विवेचनाधिकारी कानून के अनुसार तैयार कर सकता है। अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में थाना में तैयार किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में अभियुक्तों द्वारा दिए जा रहे उस विशेष बयान को विश्वसनीयता प्रदान की जा सके। **बॉबी बनाम केरल राज्य 2023, (1) एस.सी.आर. 335**, के मामले में भी भरोसा किया जा सकता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम वर्ष 1872 की धारा 27 के तहत अभियुक्त के इकबालिया बयान को दर्ज न करने के अभाव में अपराध से संबंधित लेखों की बरामदगी पर भरोसा करने से इनकार कर दिया।

64. वाहिद (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में साक्ष्य की मूल्यांकन करने के मानकों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं जहां अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है:

"14. ऐसे मामलों में जहां अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और आरोपी बनाए गए व्यक्तियों को गवाहों के बारे में पता नहीं होता है, विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय मामला है या नहीं। इस प्रकार के मामलों में, अदालतों को इस संबंध में सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है (ए) जांच एजेंसी ने अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में कैसे सुराग प्राप्त किया; (ख) अभियुक्त को किस प्रकार गिरफ्तार किया गया; और (ग) जिस तरह से आरोपी की पहचान की गई। उपरोक्त के अलावा, अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण पर या उसके कहने पर, या उसके कब्जे से किसी भी लूटी गई वस्तु की खोज/बरामदगी, अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए महत्व रखती है।



65. संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने कथित रूप से बरामदगी के बारे में सबूतों को ठोस और विश्वसनीय नहीं पाया और बरामदगी को खारिज कर दिया और केवल चश्मदीद गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। हालांकि, अभिलेखों पर उपलब्ध सबूतों और आसपास की पूरी परिस्थितियों की जांच के बाद, हम पाते हैं कि अभिलेखों पर कोई मजबूत, ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं आया है जो यह दर्शाता हो कि चश्मदीद गवाह आरोपी की पहचान करने में सक्षम थे। कानून के सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं होता है, तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा।

66. यह पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित अन्वेषण एजेंसी का पवित्र कर्तव्य है कि जहाँ तीन व्यक्तियों की मृत्यु एवं एक अन्य व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने जैसे जघन्य अपराध का आरोप हो, वहाँ पुलिस द्वारा अत्यंत सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक अन्वेषण किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम समयबद्ध रूप से उठाए जाने चाहिए कि अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही अथवा शिथिल एवं उदासीन दृष्टिकोण के कारण किसी भी प्रकार का साक्ष्य नष्ट न हो। तथापि, इस प्रकरण में यह न्यायालय यह अभिलिखित करने के लिए विवश है कि अन्वेषण में गंभीर त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं तथा पुलिस ने अपने कर्तव्यों का विधिवत् एवं समुचित निर्वहन नहीं किया है। अन्वेषण अनेक कमियों से ग्रस्त है, जिनमें रक्त-रंजित वस्त्रों एवं लाठियों की बरामदगी के बावजूद फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त न किया जाना, पूर्व-समयांकित (ante-timed) प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी में विलंब, दोषपूर्ण बरामदगी पंचनामे, गिरफ्तारी के समय को लेकर विवाद, तथा अ०सा०-1 और अ०सा०-2 को अभियुक्तों एवं बरामद वस्तुओं की पहचान हेतु बुलाने में पुलिस अधिकारियों की विफलता सहित अन्य त्रुटियाँ सम्मिलित हैं।

67. अंत में, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता की दलील थी कि विचारण न्यायालय ने धारा 396 भ०द०वि० के तहत तीन आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने में गलती की, जबकि धारा 396 भ०द०वि० को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता है। अपीलकर्ताओं की इस दलील के आलोक में, अभियोजन पक्ष के मामले को धारा 396 भ०द०वि० के अपराध के अवयवों की कसौटी पर आंका जाना चाहिए।



68. माना जाता है कि धारा 396/412 भ०द०वि० के तहत तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और सत्र न्यायालय में मामला दर्ज करने के बाद, तीन आरोपियों के खिलाफ शुरू में आरोप भी तय किया गया था। हालांकि, बाद में इसके विकास पर, दो और अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करने के लिए जोड़ा गया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अवर न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया, जो अब अपीलकर्ता हैं, जबकि एक को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। हमारे सामने विचार के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या विचारण न्यायालय ने धारा 396 भ०द०वि० के तहत चार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में गलती की थी। इस प्रयोजन के लिए, धारा 391 भ०द०वि० जो डकैती को परिभाषित करती है और धारा 396 भ०द०वि० को इसके साथ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"391. डकैती- जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहां डकैती करने या करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पूरी संख्या, और उपस्थित और इस तरह के कमीशन या प्रयास में सहायता करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच या अधिक होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह से प्रतिबद्ध है, प्रयास करता है या सहायता करता है, उसे "डकैती" करने के लिए कहा जाता है।

396. हत्या के साथ डकैती- यदि पांच या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहा है, इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या करता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

69. अपीलकर्ताओं ने मनमीत (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देकर भरोसा किया है, जिसमें न्यायालय ने धारा 396 भ०द०वि० की अनिवार्यताओं के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

"33. उपरोक्त घोषणाएं धारा 149, भ०द०वि० की धारा 396 भ०द०वि० में निहित सामूहिक अपराध की अवधारणा के विस्तार को स्वीकार करती हैं, जो डकैती के साथ हत्या पर विचार करती हैं। इस प्रकार अपराध में भाग लेने वाले पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जमावड़ा धारा 396 भ०द०वि० के तहत अपराध के लिए अनिवार्य शर्त है, जो किसी एक या एक से अधिक सदस्यों को दोषी ठहराने की अनुमति देता है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भले ही अन्य को उनकी पहचान के अभाव में बरी कर दिया जाए। हत्या के साथ डकैती करने के सामान्य उद्देश्य से प्रभावित पांच या अधिक व्यक्तियों के इस तरह के जमावड़े के अभाव में, उसके किसी भी सदस्य को उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही उसकी हत्या का व्यक्तिगत कार्य कुछ भी हो, जब तक कि उस अपराध के लिए स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से आरोप न लगाया गया हो।

34. जैसा कि ऊपर दिए गए विज्ञापन के अनुसार, अभियोजन पक्ष इस मामले में अपराध के गठन में पांच या अधिक व्यक्तियों की भागीदारी को साबित करने या उनकी पहचान स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302 भ०द०वि० के तहत एक ही आरोप के अभाव में, हम बेझिझक राय रखते हैं कि हत्या के साथ डकैती के लिए उसकी दोषसिद्धि भ०द०वि० की धारा 396 के तहत दंडनीय है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। हम समझते हैं कि अवर न्यायालयों का ध्यान मामले के इस महत्वपूर्ण और निर्धारक पहलू की ओर आकर्षित नहीं किया गया था।

(महत्व सन्निविष्ट)

70. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने राज कुमार (उपरोक्त) पर अवलंबन किया है जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी थी:

"15. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। यह विवाद में नहीं है कि छह व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन यहां तक कि विचारण न्यायालय भी सभी अभियुक्तों की मिलीभगत के बारे में अभियोजन पक्ष के सबूतों से आश्वस्त नहीं था और उनमें से दो को संदेह का लाभ प्रदान किया गया था। यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि डकैती करने वाले छह व्यक्ति थे और उनमें से दो अभियुक्तों की पहचान नहीं की जा सकी लेकिन शेष चार की पहचान की गई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह साबित हो गया था कि छह आरोपी थे और उन सभी ने डकैती का अपराध किया था, लेकिन पहचान के रूप में अपर्याप्त सबूतों को देखते हुए, उनमें से



दो को बरी करने की आवश्यकता थी। ऐसे मामले में, पांच से कम अभियुक्तों की दोषसिद्धि को कानून के अनुसार बनाए रखा जा सकता है। लेकिन, एक बार जब न्यायालय छह में से दो अभियुक्तों की उपस्थिति और भागीदारी पर संदेह करता है और उन्हें लाभ प्रदान करता है, तो पांच से कम व्यक्ति होते हैं और उनके खिलाफ धारा 396 भ०द०वि० के तहत अपराध के लिए कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। आइए इस पहलू पर कानूनी स्थिति पर विचार करें।

XXX

21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डकैती के अपराध की दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए, पांच या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, एक आरोपी को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, किसी दिए गए मामले में, ऐसा हो सकता है कि पांच या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं और पांच या अधिक व्यक्तियों का तथ्य या तो विवादित नहीं है या स्पष्ट रूप से स्थापित है, लेकिन न्यायालय उन सभी व्यक्तियों की पहचान के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज करने में सक्षम नहीं हो सकता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डकैती की है और उन्हें दोषी ठहराने में सक्षम नहीं हो सकता है और उन्हें बरी करने का आदेश नहीं दे सकता है, यह देखते हुए कि उनकी पहचान स्थापित नहीं है। ऐसे मामले में, पांच से कम व्यक्तियों या यहां तक कि एक - की सजा भी कायम रह सकती है। लेकिन इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, डकैती के अपराध के लिए पांच से कम व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

XXX

35. प्रस्तुत मामले में, जैसा कि पहले देखा गया था, छह आरोपी थे। उन छह आरोपियों में से दो को अवर न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किए बिना बरी कर दिया कि डकैती का अपराध छह व्यक्तियों द्वारा किया गया था, लेकिन दो आरोपियों की पहचान स्थापित नहीं की जा सकी। उन्हें न्यायालय ने बस बरी कर दिया था। इसलिए, हमारी राय में, स्थापित कानून के अनुसार, चार व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जो पांच से कम है जो डकैती करने के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके अलावा, उन सभी को धारा 120 बी भ०द०वि० के तहत दंडनीय



आपराधिक साजिश के अपराध के साथ-साथ धारा 412 भ०द०वि० के तहत दंडनीय डकैती के कमीशन में चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए बरी कर दिया गया था। इसलिए, धारा 396 भ०द०वि० के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कायम नहीं हो सकती है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(महत्व सन्निविष्ट)

71. इस प्रकार, धारा 396 भ०द०वि० के तहत एक अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक है कि पांच या अधिक व्यक्तियों को डकैती के कमीशन के लिए एक साथ आना चाहिए और डकैती के कमीशन के दौरान, उक्त पांच व्यक्तियों में से एक या अधिक ने धारा 302 भ०द०वि० के अर्थ के भीतर हत्या की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विषय अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है और इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज किए बिना, अपीलकर्ताओं को धारा 396 भ०द०वि० के तहत दोषी ठहराया है, जो स्पष्ट रूप से कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है और धारा 396 की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता है।

72. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करना होगा और यदि अभियुक्त अभियोजन पक्ष की कहानी में उचित संदेह पैदा करने में सफल हो जाता है, तो अभियुक्त को लाभ से बचा लिया जाएगा। संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन यह सबूतों की जगह नहीं ले सकता। अभिलेखों पर सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों के विश्लेषण से, यह उचित संदेह से परे स्थापित होता है कि एक अपराध हुआ था, लेकिन यह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है कि कथित अपराध आरोपी द्वारा किया गया था।

निष्कर्ष:-

73. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता की कसौटी पर अभियोजन पक्ष के मामले का निर्णय लेने पर, यह अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध की खोज दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक अयोग्य और अनारक्षित संतुष्टि उत्पन्न नहीं करता है। समग्र रूप से अभिलेखों पर उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के यह मानती है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कई अपूरणीय विसंगतियों, विसंगतियों और चूकों को नजरअंदाज करके



अभियोजन पक्ष के पक्ष में अस्वाभाविक रूप से फैले हुए हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला श्रेय के योग्य नहीं हो जाता है। इस न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को कानून में बाध्य साबित करने में विफल रहा है, और इसलिए, वे संदेह का लाभ दिए जाने के हकदार हैं।

74. तदनुसार, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी जाती है। दिनांक 13.10.2009 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, उन्नाव द्वारा पारित दिनांक 13.10.2009 की सजा की मात्रा के आदेश को रद्द/अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को धारा 396 भ०द०वि० के तहत दंडनीय अपराधों से बरी कर दिया जाता है। अपीलकर्ताओं को हिरासत से तुरंत रिहा किया जा सकता है, यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए बांड के निष्पादन पर, जो धारा 437ए द०प्र०स० के संदर्भ में छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।

75. सभी लंबित आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

76. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेखों के साथ तत्काल विचारण न्यायालय को भेजी जाए। निर्णय की एक प्रति, यदि आवेदन के लिए आवेदन किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

77. हम श्री हरीश चंद्र, एमिक्स क्यूरी/न्याय मित्र द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हैं, और हम उनके पारिश्रमिक के लिए 30,000/- रुपये (केवल तीस हजार) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

दिनांक: 29.01.2026 / रीना

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी)

(न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मोईन)